

Daily Current Affairs

Date : 30 September, 2025



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	जयपुर में 'स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना'
2.	64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार
3.	देश के 'अति दोहित' जिलों में राजस्थान के 29 जिले शामिल
4.	स्कूल शिक्षा विभाग को गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड-2025
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. चाणक्य एक्सीलेंस इन मीडिया एजुकेशन अवॉर्ड : डॉ.सारिका ताखर 2. देसूला ग्राम पंचायत 3. ओपी शर्मा - आकाशवाणी सांख्यिकीविद् नियुक्त 4. नार्चीकॉन - 2025 5. जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जीटो) 6. राजस्थान सीनियर पुरुष बॉक्सिंग चैम्पियनशिप-2025
6.	सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958
7.	भारत में शहरी क्षेत्र की परिभाषा
8.	फार्मास्युटिकल दवाओं पर 100% टैरिफ: अमेरिका
9.	G4, L.69 और C-10
10.	रूस-ईरान परमाणु संयंत्र समझौता
11.	कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE) मानक
12.	अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज
13.	दिनांकित प्रतिभूतियां और सॉवरेन ग्रीन बांड्स (SGrBs)
14.	पुरुष क्रिकेट एशिया कप, 2025

--:1:--



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR



जयपुर में 'स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना'



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जयपुर नगर निगम क्षेत्र में निजी आवासीय भवनों की छतों पर सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना' की शुरुआत की गई।



मुख्य बिन्दु:

- इस परियोजना की शुरुआत दुर्गापुरा (जयपुर) स्थित अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्र (IHITC) द्वारा की गई है।
- इस योजना के दायरे में केवल जयपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित निजी आवास आएंगे तथा केवल जयपुर नगर निगम क्षेत्र के निजी आवासीय भवनों के मालिक ही आवेदन कर सकते हैं।

Daily Current Affairs

Date : 30 September, 2025



- योजना में केवल 3 मंजिला तक भवन शामिल होंगे जहाँ मकान की छत 200 वर्ग फीट तथा सक्रिय नल कनेक्शन होना आवश्यक है।
- रूफ टॉप यूनिट निर्माण की कुल अनुमानित लागत : ₹53,619
- इस योजना के तहत 70 प्रतिशत की राशि अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जबकि शेष 30 प्रतिशत राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान में बागवानी से संबंधित प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र:

क्रमांक	केन्द्र का नाम	जिला	स्वीकृत वर्ष
1.	सिट्रस उत्कृष्टता केन्द्र	नान्ता, कोटा	2012-13
2.	अनार, जैतून (Olive), ड्रेगन फ्रुट उत्कृष्टता केन्द्र	बस्सी, जयपुर	2012-13
3.	खजूर उत्कृष्टता केन्द्र	सगरा भोजका, जैसलमेर	2012-13
4.	अमरूद उत्कृष्टता केन्द्र	देवडावास, टोंक	2014-15
5.	संतरा उत्कृष्टता केन्द्र	झालावाड	2014-15
6.	आम उत्कृष्टता केन्द्र	खेमरी, धौलपुर	2014-15
7.	सब्जी फसलों का उत्कृष्टता केन्द्र	बून्दी	2016-17
8.	फूलों का उत्कृष्टता केन्द्र	सवाई माधोपुर	2016-17
9.	सीताफल उत्कृष्टता केन्द्र	चित्तौड़गढ़	2016-17

--3--

64वाँ राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के 2 व्यक्तित्वों को 64वें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



मुख्य बिन्दु:

राजस्थान के पुरस्कार विजेता :

नाम	क्षेत्र	जिला
डॉ. गिरिराज शर्मा	मूर्ति कला	जयपुर
डॉ. कनुप्रिया	मिक्स्ड मीडिया	पाली



- आयोजन : नई दिल्ली में।
- ललित कला अकादमी कला को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए हर साल कला प्रदर्शनियों और पुरस्कार समारोहों का आयोजन करती है।
- ललित कला अकादमी का उद्घाटन 5 अगस्त, 1954 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था।

- मुख्यालय : नई दिल्ली।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तित्व :

- बेगम बतूल (कला) - नागौर।
- बैजनाथ महाराज (अध्यात्म) - सीकर।
- शीन काफ निजाम (शिव किशन बिस्सा) (साहित्य) - जोधपुर।
- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार - 2025
- नीलम यादव - राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, टपूकड़ा (खैरथल-तिजारा)।
- राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार - 2024
- राधे लाल शर्मा (क्लीनिकल नर्स श्रेणी) - वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, ट्रौमा सेंटर, सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर।

देश के 'अति दोहित' जिलों में राजस्थान के 29 जिले शामिल

चर्चा में क्यों?

- जल शक्ति मंत्रालय के "जल शक्ति अभियान : कैच द रेन-2025" (JSA:CTR-2025) के अंतर्गत देश के 'अति शोषित' जिलों में राजस्थान के 29 जिले शामिल हैं।



मुख्य बिन्दु:

- **JSA:CTR 2025 की विषयवस्तु** : "जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर"।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा वर्ष 2025 के लिए देश के 148 जिलों को 'अति-दोहित', 'गंभीर' और 'अर्ध-गंभीर' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इन जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर गहन जुड़ाव, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण और नवीन वित्तपोषण तंत्र पर जोर दिया जा रहा है।
- जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 में देश के 256 जल-संकटग्रस्त जिलों में जल शक्ति अभियान (JSA) शुरू किया गया। इसी क्रम में प्रधान मंत्री ने वर्ष 2021 में "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (JSA: CTR) की शुरुआत "कैच द रेन - व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स" टैगलाइन के साथ की।

Daily Current Affairs

Date : 30 September, 2025



- वर्ष 2022 से केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) और राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष संयुक्त रूप से देश के गतिशील भूजल संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है।
- CGWB द्वारा जारी की गई "भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन, 2024" रिपोर्ट के अनुसार, देश के 102 जिलों को 'अति-दोहित', 22 जिलों को 'गंभीर' और 69 जिलों को "अर्ध-गंभीर" श्रेणी में रखा गया है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

मनरेगा कार्यों में जल संरक्षण गतिविधियाँ:

- हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार कार्ययोजना के तहत 'अति जल संकट ग्रस्त' और 'गंभीर जल संकट' वाले ग्रामीण ब्लॉकों में मनरेगा राशि का 30 से 65 प्रतिशत कार्य जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा।
- इस कार्ययोजना के लागू होने से राजस्थान जैसे जल संकट से ग्रसित राज्यों को लाभ होगा।
- इस कार्ययोजना के अंतर्गत अर्ध-गंभीर ग्रामीण ब्लॉकों में मनरेगा राशि का 40 प्रतिशत खर्च किया जाएगा जबकि जिन ब्लॉकों में जल संकट ज्यादा नहीं है, वहाँ मनरेगा व्यय के अंतर्गत 30 प्रतिशत राशि जल संबंधी कार्यों पर खर्च होगी।

--6--

स्कूल शिक्षा विभाग को गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड-2025

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षा क्षेत्र में डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड, 2025 से सम्मानित किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट समारोह में राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड प्राप्त किया। ये पुरस्कार स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन एवं स्कॉच डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर कोचर ने प्रदान किया।
- ज्ञातव्य है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने स्कूल स्तर पर हेल्थ चेकअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है।

Daily Current Affairs

Date : 30 September, 2025



- इस पहल का उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग करना और उन्हें समय पर चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराना है। साथ ही, इस पहल के तहत सरकारी विद्यालयों के छात्रों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान :

- राजस्थान में "शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान" स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जाँच करना और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।
- यह स्वास्थ्य परीक्षण एक मोबाइल ऐप और शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जहाँ 70 प्रश्नों के आधार पर पेपरलेस सर्वेक्षण किया जाता है। इस अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, गंभीर बीमारियों का पता लगाया जाता है और निशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाती है।

--8--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>चाणक्य एक्सीलेंस इन मीडिया एजुकेशन अवॉर्ड : डॉ. सारिका ताखर</p> <ul style="list-style-type: none">निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर की मीडिया स्टडीज विभाग की डीन डॉ. सारिका ताखर को हाल ही में पब्लिक रिलेशन्स काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 'चाणक्य एक्सीलेंस इन मीडिया एजुकेशन अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।उन्हें यह सम्मान मीडिया स्टडीज के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट योगदान और नवाचार के लिए गोवा में आयोजित 19वीं ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में प्रदान किया गया।
2.	<p>देसूला ग्राम पंचायत</p> <ul style="list-style-type: none">अलवर जिले की देसूला ग्राम पंचायत देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है, जहाँ सभी निवासियों को बीमा कवर प्रदान किया गया है।
3.	<p>ओपी शर्मा - आकाशवाणी सांख्यिकीविद् नियुक्त</p> <ul style="list-style-type: none">गुवाहाटी में होने वाले महिला विश्व कप के भारत-श्रीलंका मैच में राजस्थान के ओपी शर्मा को आकाशवाणी सांख्यिकीविद् नियुक्त किया गया।
4.	<p>नार्चीकॉन - 2025</p> <ul style="list-style-type: none">नेशनल एसोसिएशन फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ऑफ इंडिया (NARCHI) का 16वाँ विश्व कांग्रेस और 24वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में 19 से 21 सितंबर, 2025 तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को 'नार्चीकॉन - 2025' नाम दिया गया।आयोजन स्थल : राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर।सम्मेलन का विषय : "मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल में नवाचार : शोध से प्रथा तक"।

5.

जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जीटो)

- हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जीटो) के 'जीटो कनेक्ट 2025' पोस्टर का विमोचन किया।

6.

राजस्थान सीनियर पुरुष बॉक्सिंग चैम्पियनशिप-2025

- 9 से 11 अक्टूबर, 2025 तक जोधपुर में 'राजस्थान सीनियर पुरुष बॉक्सिंग चैम्पियनशिप' का आयोजन किया जाएगा।
- प्रतियोगिता में राजस्थान के 24 जिलों के 200 मुक्केबाज, 50 कोच मैनेजर और 25 तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे।





सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA), 1958



चर्चा में क्यों?

- गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में AFSPA की अवधि में वृद्धि की।



मुख्य बिन्दु:

- केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत मणिपुर राज्य के 13 पुलिस थानों के क्षेत्र को छोड़कर, पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है। इसकी अवधि छह महीने तक बढ़ा दी गई है।
- **अशांत क्षेत्र:** AFSPA अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है।
- जब किसी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के कुछ क्षेत्र या पूरे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है, तब उस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के कुछ क्षेत्र या पूरे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है।
- किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' राज्य के राज्यपाल/ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है।

अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को AFSPA के तहत प्राप्त अधिकार:

- किसी क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक लोगों की भीड़ को प्रतिबंधित करने का अधिकार।
- उचित संदेह होने पर सेना को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार।
- बिना वारंट के किसी घर या परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार।
- हथियारों के भंडार, किलेबंद स्थान जहाँ से सशस्त्र हमले किए जा सकते हैं, या हथियारबंद स्वयंसेवियों के प्रशिक्षण शिविर को नष्ट करने का अधिकार।
- **कानून जहाँ पर लागू है:** अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।

भारत में शहरी क्षेत्र की परिभाषा

चर्चा में क्यों?

- भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने यह प्रस्ताव किया है कि वर्ष 2027 की जनगणना में शहरी क्षेत्र की परिभाषा वही रखी जानी चाहिए, जो 2011 की जनगणना में लागू थी।

मुख्य बिन्दु:

- इसका उद्देश्य पिछली जनगणनाओं से तुलनात्मक अध्ययन करना और देश में शहरीकरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने का आधार उपलब्ध कराना है।

भारत में "शहरी क्षेत्र" की आधिकारिक परिभाषा

- भारत की जनगणना दो तरीकों से "शहरी" के रूप में वर्गीकृत करती है:-
- **वैधानिक कस्बे:** वे सभी प्रशासनिक इकाइयाँ, जिन्हें कानून द्वारा शहरी के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे- नगर निगम, नगर पालिका, छावनी परिषद, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, टाउन पंचायत, नगर पालिका आदि।
- जिन वैधानिक कस्बों की जनसंख्या 1,00,000 या उससे अधिक होती है उन्हें "शहर" की श्रेणी में रखा जाता है।
- **जनगणना कस्बे (Census Town):** ऐसे कस्बे जो वैधानिक कस्बे नहीं हैं, लेकिन तीन विशिष्ट जनसांख्यिकीय और आर्थिक मानदंडों को एक साथ पूरा करते हैं:-
- न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो।
- जनसंख्या घनत्व कम-से-कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।
- कामकाजी आबादी में से कम-से-कम 75% गैर-कृषि कार्यों में संलग्न हों।



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



फार्मास्युटिकल दवाओं पर 100% टैरिफ: अमेरिका



चर्चा में क्यों?

- 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंट वाली दवाओं के अमेरिका में आयात पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि, यदि कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी उत्पादन इकाई स्थापित कर लेती है या कर रही है, तो यह टैरिफ नहीं लगाया जाएगा।



मुख्य बिन्दु:

- भारत, जिसे अक्सर "दुनिया की फार्मेसी" कहा जाता है, विश्व के सबसे बड़े दवा निर्यातक देशों में से एक है। इसकी वैश्विक दवा बाजार में हिस्सेदारी लगभग 5.71% है।

भारत के दवा निर्यात पर टैरिफ का प्रभाव

- भारत सबसे अधिक दवाओं का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को करता है। वित्त वर्ष 2025 में लगभग 10 बिलियन डॉलर मूल्य का निर्यात किया था, जो दवाओं के कुल निर्यात का लगभग 35% हिस्सा है।
- भारत का निर्यात मुख्यतः कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) का है, जो टैरिफ के दायरे से बाहर हैं।

भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र

- स्थिति:** दवाओं के उत्पादन में भारत दुनिया भर में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 11वें स्थान पर है।
- विकास क्षमता:** इस उद्योग के 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- निर्यात:** भारत मुख्य रूप से ड्रग फॉर्मूलेशंस और बायोलॉजिकल्स का निर्यात करता है, जो भारत के कुल दवा निर्यात का लगभग 75% हिस्सा हैं।
- वैश्विक टीका उत्पादन में भारत 60 प्रतिशत का योगदान करता है।

G4, L.69 और C-10

चर्चा में क्यों?

- G4 सदस्य देशों के मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- भारत के विदेश मंत्री ने L.69 समूह और C-10 की संयुक्त बैठक भी आयोजित की।

मुख्य बिन्दु:

G4 (ग्रुप ऑफ फोर)

- **सदस्य:** ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान।
- **उद्देश्य:** UNSC की स्थायी सदस्यता के प्रयासों में एक-दूसरे का समर्थन करना।

L.69 समूह

- **सदस्य:** अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, प्रशांत क्षेत्र के 40 से अधिक विकासशील देश। इनमें भारत भी शामिल है।
- **उद्देश्य:** विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ UNSC के व्यापक सुधार को आगे बढ़ाना।

C-10 (दस देशों की समिति)

- **सदस्य:** अफ्रीकी संघ के 10 देश - अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो, केन्या, लीबिया, नामीबिया, सेनेगल, सियरा लियोन, युगांडा और जाम्बिया।
- **उद्देश्य:** UNSC में सुधार पर अफ्रीका के साझा पक्ष का प्रतिनिधित्व करना।

रूस-ईरान परमाणु संयंत्र समझौता

चर्चा में क्यों?

- ईरान की हॉर्मोज़ कंपनी और रोसाटॉम के बीच सीरिक (हॉर्मोज़गन प्रांत) में 25 बिलियन डॉलर के मूल्य पर चार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

- प्रत्येक संयंत्र की क्षमता 1,255 मेगावाट होगी।
- वर्तमान में ईरान के पास सिर्फ एक चालू परमाणु संयंत्र है, जो बुशहर में स्थित है।

ईरान के प्रमुख परमाणु स्थल:

- नांताज़ संवर्धन परिसर
- फोर्दो ईंधन संवर्धन संयंत्र
- इस्फ़हान यूरेनियम रूपांतरण और ईंधन निर्माण परिसर।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE) मानक

चर्चा में क्यों?

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी-3 और कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी-4 मानदंडों के मसौदे में संशोधन किया है।

मुख्य बिन्दु:

- नए मानदंडों में पहली बार छोटी कारों को विशेष राहत दी गई है, और फ्लेक्स-फ्यूल तथा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

CAFE मानदंड?

- इन्हें सबसे पहले सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 2017 में अधिसूचित किया गया था।
- **उद्देश्य:** CO₂ उत्सर्जन को कम करके ईंधन की खपत को कम करना। तेल पर निर्भरता और वायु प्रदूषण को कम करना।
- यह ड्राइवर सहित अधिकतम 9 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाली यात्री कारों और अधिकतम 3,500 किलोग्राम सकल भार वाले वाहनों पर लागू होता है।
- ये मानदंड 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2032 तक लागू रहेंगे।

आर्थिक परिदृश्य

अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज

चर्चा में क्यों?

- अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर, तटरेखा से 17 किमी दूर श्री विजयपुरम-2 कुएं में प्राकृतिक गैस खोजी गई है।

मुख्य बिन्दु:

- भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अंडमान-निकोबार बेसिन में 371 मिलियन मी ट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद हैं।
- भूगर्भीय रूप से अंडमान-निकोबार बेसिन, अंडमान और निकोबार बेसिन के संगम पर स्थित है, जो बंगाल-अराकान तलछट प्रणाली का हिस्सा है।
- भारतीय और बर्मा प्लेट्स की सीमा पर टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से यहाँ स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स निर्मित हुए हैं, जो हाइड्रोकार्बन के लिए उपयुक्त हैं।
- उत्तरी सुमात्रा (इंडोनेशिया) और इरावदी-मार्गुई (म्यांमार) में गैस की खोज की जा चुकी है।
- यह खोज भारत के 2030 तक गैस-आधारित अर्थव्यवस्था बनने में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% तक करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- वर्तमान में, भारत अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का केवल 50% उत्पादन करता है और शेष माँग आयात के जरिए पूरी करता है।

भारत की प्रमुख पहलें:

- **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP) 2016:** इसने सभी हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंसिंग ढाँचा पेश किया है। इसके तहत ओपन एकरेज लाइसेंसिंग (OALP) प्रणाली की शुरुआत की गई है।
- **नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन:** नई खोज करने और हाइड्रोकार्बन भंडार का पूरी तरह से दोहन करने के लिए अपतटीय बेसिनों में अन्वेषण कुओं की योजना बनाई गई है।
 - नेशनल डेटा रिपॉजिटरी:
 - नेशनल सीस्मिक प्रोग्राम:
- प्राकृतिक गैस क्षेत्रक में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आदि।

दिनांकित प्रतिभूतियाँ और सॉवरेन ग्रीन बांड्स (SGrBs)

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परामर्श से चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के लिए अपने उधार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। इसमें दिनांकित प्रतिभूतियाँ और सॉवरेन ग्रीन बांड्स (SGrBs) जारी करना शामिल हैं।

मुख्य बिन्दु:

दिनांकित प्रतिभूतियाँ (सरकारी बांड्स)

- **परिभाषा:** ये ऐसी प्रतिभूतियाँ हैं जिन पर एक निश्चित या परिवर्तनीय कूपन (ब्याज दर) का भुगतान किया जाता है। इनका भुगतान छमाही आधार पर अंकित मूल्य पर किया जाता है।
- **मैच्योरिटी अवधि:** इनकी मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है।
- **अन्य अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियाँ:** नकद प्रबंधन बिल (CMBs), ट्रेजरी बिल्स।
- **सॉवरेन ग्रीन बांड्स (SGrBs)**
- ये पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली अथवा अनुकूल जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त-पोषित करने हेतु जारी ऋण प्रतिभूतियाँ हैं।
- **शुरुआत:** इसे केंद्रीय बजट 2022-2023 में पेश किया गया था।



पुरुष क्रिकेट एशिया कप, 2025

चर्चा में क्यों?

- 28 सितंबर, 2025 को भारत क्रिकेट टीम ने दुबई में एशिया कप, 2025 के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराकर अपना नौवाँ खिताब जीता।



मुख्य बिन्दु:

- यह एशिया की शीर्ष टीम का निर्धारण करने के लिए द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाली महाद्वीपीय पुरुष क्रिकेट चैम्पियनशिप हैं।
- ICC द्वारा मैचों को आधिकारिक ODI या T20I का दर्जा दिया जाता है।
- आयोजक :** एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ; स्थापना : वर्ष 1983
- शुभंकर :** 'शेरू' था, जो एशियाई क्रिकेट की ताकत, साहस और एकता का प्रतीक था।
- संस्करण :** 17वाँ।

--:19:--

Daily Current Affairs

Date : 30 September, 2025



- प्रारूप : T-20 अंतरराष्ट्रीय (T-20I)।
- परिणाम : भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया।
- मैन ऑफ द मैच (फाइनल) : तिलक वर्मा (53 गेंदों पर नाबाद 69 रन)
- मैन ऑफ द सीरीज : अभिषेक शर्मा

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

एशिया कप:

- पृष्ठभूमि : वर्ष 1984 में शुरू एशिया कप एकमात्र महाद्वीपीय क्रिकेट टूर्नामेंट है।
- रिकॉर्ड : एशिया कप, 2023 (वनडे प्रारूप) जीतने के बाद यह भारत का लगातार दूसरा खिताब है।

भारत	9 खिताब (सर्वाधिक)
श्रीलंका	6 खिताब
पाकिस्तान	2 खिताब

--:20:--